

कवायदः मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल मिश्र से मुलाकात

मंत्रिमंडल विस्तार इसी माह, 10 नए चेहरों पर लग सकती है मुहर!

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net.com

जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी माह अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से रविवार को दोहरा लगाभग खटे की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकते तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार सबकुछ ट्रैक रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार इसी सप्ताह होगा। यह तय है कि फारवरी में विधायकों के बजट सत्र में गहलोत की टीम लगभग 10 नए चेहरों के साथ कुछ बदली नजर आएंगी। गहलोत अपनी टीम में कांग्रेस के 5, तीन निर्देशीयों के बासपा से कांग्रेस में शामिल 30 में से 10 विधायकों को लगभग 2-3 राज्य मंत्रियों का प्रबोधन हो सकता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग (जीएडी) को भी तैयारियों के लिए कह दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार कारोबार काल तथा सिवायी घमासान के कानून लगभग 10 महीनों से अटका हुआ है।

9 जाण खाती, पुरी गाही गाही

मंत्रिमंडल में वर्तमान में 30 में से 9 जाण खाती हैं। सूत्रों के अनुसार विस्तार में सभी खाती जान नहीं जाएंगी। सामाजिक न्याय व अधिकारियों ने अपनी विभागों को नियन्त्रण सिवायी संस्करण के बदलाव को अपनी विभागों के लिए अपनी विभागों के बदलाव को अपनी विभागों के बदलाव को दिया है। उन्हें विभागों के बदलाव को अपनी विभागों के बदलाव को दिया है।

सीएग के पास 18 से ज्यादा विभाग

अपनी गहलोत के पास 18 से अधिक विभाग हैं। पहले उक्ते पास वित्त, गृह, कांग्रेस जैसे अपने विभागों के साथ 9 विभाग थे। इन सिवायी घमासान के बाइंग संचयन पालामूल, संसेध जीएग एवं विवेक

गुरुगंगांवी ने संशोधन प्रस्तावों को दी गंगुरी विवाह पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान, जन्म रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ेगी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.in.com,

जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शादियों के राजस्त्रैशन तथा जन्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं में सुधार कर इने आसान बनाने का निर्णय लिया है। इसमें राजस्त्रैशन में विवाह अधिनियम तथा जन्म पंजीकरण के नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा सकेगी। गहलोत ने इसके लिए राजस्त्रैशन विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, 2009 और राजस्त्रैशन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, 2000 में जरूरी संशोधन करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आयोजना एवं सांघिकीकृत विवाह के प्रस्तावों के अनुसार, राजस्त्रैशन विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2009 में प्रस्तावित संशोधन कर राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में जिला विवाह रजिस्ट्रेशन कर्तव्यान्वयन के साथ-साथ अवधारणा का अनुसार, राजस्त्रैशन अतिरिक्त जिला विवाह अधिकारी और बालक विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त विवाहों जापानी की अयु और रजिस्ट्रेशन के लिए जापान की विधि आदि से संबंधित संशोधन कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

देना होगा विलम्ब शुल्क

इसी प्रकार, राजस्त्रैशन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2000 में संशोधन कर राज्य आयोजना एवं सांघिकीकृत विभागों के एक अन्य प्रत्यावर्त के अनुसार, बालक या आयोजिक के जन्म रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष से अधिक हो जाने की सिफारिश भी जिसके लिए जापान की प्रस्तावित विवाह के नए नियमों के लागू होने के पांच वर्ष बाद तक नाम दर्ज करवाए जा सकेंगे।



जगीनी फौंडेक पर कान करेगी गहलोत सरकार

कार्यकर्ता टटोलेंगे जनता की नज़

जयपुर @ जागरूक जनता। अपने कार्यकार के तीसरे साल में प्रदेश कर रुकी राज्य की अशोक गहलोत सरकार अब संगठन की सलाह और फौंडेक के आधार पर काम करेगी और जिसीनी फौंडेक से नियन्त्रित कर आई माना और सुझावों पर प्रयोगकर्ता से कान करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर जिला से सरकार के कामकाज का फौंडेक जुराना सरकार के भेजा जाएगा और उसी आधार पर सरकार आगे काम करेगा। सभी को माने को प्रदेश के सभी जिलों और गांव वालों में संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता सरकार के दो साल के कामकाज का लेकर जनता में कार्य प्रसिद्धि या है, इसका फौंडेक लेकर प्रदेश कांग्रेस को भेजें। जिसके प्रश्नों पर जवाब देने के लिए जिला विवाह करेगा। उन्होंने जिला विवाह के लिए राजनीति एवं सरकार को भेजे। सरकार के कामकाज के फौंडेक जुराना का जिम्मा विवाह कांग्रेस ने नहान ठिकाने की दिया है।

सिंह को भी प्रसंग से देखा गया। वहीं, लम्बी बीमारी के बाद हाल में बंदरगाह में विवाह का नियन्त्रण हो गया। इस कारण पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, पौदलवृद्धि, खाद्य अधिकारिता, आपदा प्रबन्धन-साहायता जैसे अहम विभाग भी मुख्यमंत्री का दर्जा मिल सकता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है।

दो-तीन गांवियों के बिंगांग होंगे कान, रीएग नीं कान करेंगे आपनी जिग्नांदारी

मुख्यमंत्री जिलों जैसे खाती रखते हैं। सूत्रों के अनुसार विस्तार में सभी खाती जान नहीं जाएंगी। सामाजिक न्याय व अधिकारियों का प्रबोधन हो सकता है। अपने विभाग (जीएडी) को भी तैयारियों के लिए कह दिया गया है।

प्रबल दावेदार

- कांग्रेस: बुंदेल आला, हमाराम यौधारी, वीपेंद्रसिंह शेखावात, मुरारी आर्ही, पर्टीने, सामाजिक न्याय-अधिकारिता, आपदा प्रबन्धन-साहायता जैसे कुछ विवाह की जिम्मेदारी खुद से टक्कर दीवान का सीधा जानकारी देता है।

- बसपा से शामिल हुए: राजद गुद्या व जागेंद्रसिंह अवाना।

मुख्यमंत्री गहलोत ने की घोषणा

देर रात तक खुलेंगे बाजार, सामाजिक कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी नहीं

जागरूक जनता नेटवर्क

jagrukjanta.in.com,

जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शादियों के राजस्त्रैशन तथा जन्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं में सुधार कर इने आसान बनाने का निर्णय लिया है। इसमें राजस्त्रैशन में विवाह अधिनियम तथा जन्म पंजीकरण के नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा सकेगी। गहलोत ने इसके लिए राजस्त्रैशन विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, 2009 और राजस्त्रैशन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, 2000 में जरूरी संशोधन करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आयोजना एवं सांघिकीकृत विवाह के प्रस्तावों के अनुसार, राजस्त्रैशन विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2009 में प्रस्तावित संशोधन कर राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में जिला विवाह रजिस्ट्रेशन कर्तव्यान्वयन के साथ-साथ अवधारणा का अनुसार, राजस्त्रैशन अतिरिक्त जिला विवाह अधिकारी और बालक विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त विवाहों जापानी की अयु और रजिस्ट्रेशन के लिए जापान की विधि आदि से संबंधित संशोधन कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।



हैल्प्ट प्रोटोकॉल्स को अपनाए रखना आवश्यक है, नहीं तो पुनः संकेतिष्ठ संख्या बढ़ सकती है। यदि वह नैवेत आई, तो वापस सख्ती करी पड़ सकती है। आयोजित के लिए अब 800 की जगह 500 रुपय में ही आर्ही-पीसीआर जांच हो जाएगी। हालांकि इनमें शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या का नियम लागू रहेगा। वहीं, जिजो लोग में फौंडेक के लिए अब 800 की जगह 500 रुपय में ही आर्ही-पीसीआर जांच हो जाएगी। वाले लोगों की अधिकतम संख्या का नियम लागू रहेगा। वहीं, जिजो लोग में अप्रकाशित आर्ही और फौंडेक बैंड की संख्या 40 फौसदी से घटकर न्यूनतम 10 प्रतिशत कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये नियमों को इनोवेट करने के लिए विवाह के बदलाव के सदस्यों से चर्चा कीर्तन की दिया है। इसके लिए जिला विवाह के बदलाव के सदस्यों को इनोवेट करने के लिए जिला सक्रमण को रोकने के लिए गत 21 नवंबर को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कार्पूर की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के तहत इन शाहरों में बाजार, रस्टोरेंट, शामिंग मॉल एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल शाम 7 बजे तक ही खोले रखेंगे के आदेश थे।

जागरूक जनता jagrukjanta.com फेसबुक पेज

पढ़े, जुड़े और बढ़े अपडेट

हर खबर से आपको रखें जागरूक जनता

प्रदेश कांग्रेस को कुशल वक्ता-प्रवक्ताओं की तलाश, रिसर्च विंग भी होगी तैनात

सरकार और पार्टी के कामकाज को जनता के बीच ले जाने का जिम्मा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net.com

जयपुर प्रदेश कांग्रेस में नवाचारित कार्यकारियों की विशेषता या बालक विवाह की विभागों के एक अन्य प्रत्यावर्त के अनुसार, बालक या आयोजिक के जन्म रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष से अधिक हो जाने की सिफारिश भी जिसके लिए जापान की प्रस्तावित विवाह के नए न

जागरूक
न्यूज़

किसान आंदोलन

एससी की गठित कमेटी की किसान नेताओं से पहली बैठक कल

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net/.com

नई दिल्ली। तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते की रात 2 महीने से जगज्ञानी दिल्ली के बॉर्डर हजारों ने समाज धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार किसानों के साथ 9 दौर की बातचीत भी कर चुकी है, लेकिन अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच यह मामला सूरीम कोट भी पहुंच चुका है और अदालत ने किसानों के बीच कानूनों को खाली करने के लिए तीनों नए कृषि कानूनों के लागू करने पर रोक लगा दी है और एक कमेटी गठित की है, जो दोनों पक्षों से बातचीत कर एक रिपोर्ट कोट की सौंपेगी। अब सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित की गई कमेटी की पहली बैठक 21 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य अनिल घावत ने बताया कि अदालत ने दो बातें ये निर्देश दिया है कि किसान संगठनों (कृषि कानून के समर्थक और विरोधी) के प्रतिनिधियों की बातें सुनान हैं और एक रिपोर्ट तैयार कर कोट को भेजनी है।

उहाँने मंगलवार के बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हुआ है कि किसानों के साथ 21 जनवरी को सुबह 11 बजे पहली बैठक होगी। इस बैठक में यदि किसी किसान संगठन के प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं तो हम वीडियो कॉफरेंस के जरिए उनकी बातें जानेंगे। अनिल घावत ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार हमारे साथ आना या बोलना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम सरकार का भी पक्ष सुनेंगे और फिर इस गतिरोध को खत्म करने के लिए अपने सर वर्षोंच्च प्रयास करेंगे।

लाल किले में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 26 तक दर्शकों के लिए रोक

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net/.com

नई दिल्ली। देश में बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। इसी की नतीजा है कि बर्ड फ्लू का प्रभाव स्थिर राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचा है। लाल किले में मृत पाए गए कौओं के सैंपल से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जिसके बाद प्रशासन ने स्पाइक भवन में लागों के प्रेसरेस पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर संस्थान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों लाल किले में लाग्याम पंद्रह कोंके मृत पाए गए थे। बर्ड फ्लू होने की आशंका के चलते पश्चिमों के सैंपल जलांधर स्थित लैब में पिछाए गए। मानवानांक को आइ रिपोर्ट में मृत कोंकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। जिसके चलते अहंत्रियत के तौर पर लाल किले को दर्शकों के लिए गणतंत्र दिवस तक के लिए बंद कर दिया गया।

हाउसिंग बोर्ड: भिवाड़ी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनेंगे करीब 700 फ्लैट्स

जयपुर में पहली बार बनाए जाएंगे स्टूडियो अपार्टमेंट, मेड्ता में सभी वर्गों के लिए बनेंगे 743 मकान

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net/.com

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पहली बार नए कॉन्सप्ट पर आवासीय योजना लाने जा रहा है। बोर्ड अब पहली बार स्टूडियो अपार्टमेंट बनाएगा। ये अपार्टमेंट जयपुर के प्रतप नगर में बनाए जाएंगे। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड नागार जिले के मेड्ता में 743 आवासों की योजना लाने की भी वीडियो कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिशन पन्न अरोड़ा ने बताया कि नागार में प्रस्तावित इस योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के 224, LIG के 158, MIG-A के 212, MIG-B के 233 और HIG के 16 मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा अलावर के भिवाड़ी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत करीब 700 फ्लैट्स बनाने की योजना है। जल्द ही इन योजनाओं को लॉन्च करके आवेदन मार्ग जारी किया जाएगा।

**कोवीशील्ड की पहली खेप
आज मालदीव पहुंचेगी**

वॉशिंगटन/लंदन/रिया डि जेनेरियो। कोरोना की वैक्सीन कोवीशील्ड की पहली खेप बुधवार को भारत से मात्रान्वत पहुंचेगी। मालदीव पहली देश है। भारत ने अपने यह वैक्सीन भेजी जा रही है। भारत ने अपने

**भारत से
वैक्सीन पाने
वाला पहला
देश होगा**

आबादी लग्याम 45 लाख है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, कोवीशील्ड को मालदीव में रेस्टोरी के अफ्लॉल से लेकर दूसरी जरूरी दी जा चुकी हैं। फॉल्डिंग हेथ्य वर्कर्स और सीनियर सिटीज़न्स के लिए इसे पर्याप्त मात्रा में भेजा जा रहा है। यह खेप एयर ड्रिंग की वाली के वैक्सीन को लगाना दिर्लेसनल एपर्योर्प पर दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कई पड़ोसी और खास सहयोगी देशों से भारत में बनी वैक्सीन की सलाइ के लिए सरकार से गुराश की है। इसके तहत 20 जनवरी से भूतान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, स्थानीय और वैक्सीन की श्रीलंका से भारत में बनी वैक्सीनों को इंतजार कर रहे हैं।

जागरूक जनता नेटवर्क/jagrukjanta.net/.com

जयपुर, बुधवार, 20 जनवरी, 2021 - 26 जनवरी, 2021

राजस्थान की आबकारी नीति में बड़े बदलाव की तैयारी एक ही दुकान से बिकेगी देशी-अंग्रेजी शराब और बीयर!

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net/.com

जयपुर। राजस्थान की नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसके लिए विभाग से सभी जिलों से रिपोर्ट मंगा ली है। इसके तहत सभी अंग्रेजी वर्ग देशी शराब दुकानों को कम्पनिट रिया दिया जाएगा। यानी देशी-अंग्रेजी शराब और बीयर, सभी की बिक्री एक साथ होगी। प्रत्येक दुकान की गारंटी राशि इन तीनों से मिलने वाली राशि को जोड़कर तय की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार नई नीति में शराब में कुछ दुकानों का कम की जा सकती है। कोरोना संक्रमण के मूदें जुड़ते हुए एक राशि रुपये देशी शराब की जाएगी। अंग्रेजी शराब दुकानों का आवंतन एक-एक कर लॉटरी के जरूर किया जाता है। जिसकी देशी शराब के लिए बाजार क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में शाम परावर्त वार समझ बना रखे हैं। एक समूह में देशी शराब की दो से तीन दुकानें हैं। नई व्यवस्था में अंग्रेजी शराब दुकानों की तर्ज पर सभी दुकानों को कम्पनिट कर एक-एक कर लॉटरी की ई-नीलामी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार दुकानों की ई-नीलामी इस्पात मंत्रालय के एमसटीसी पोर्टल से की जाएगी।



राज्य में शराब की तीनी दुकानें

- 1000 दुकानें अंग्रेजी शराब की
- 6600 दुकानें देशी शराब की
- 1191 दुकानें देशी शराब लॉटरी में शेयर ग्रामीण में
- 206 दुकानें अंग्रेजी और 300 दुकानें देशी शराब की हैं जयपुर में

पिछले साल ही नई आबकारी नीति जारी की गयी थी। इसमें दुकानों का एक साल के लिए और नवांचिकरण करने का प्रावधान किया गया था। लैकिन वर्ष बदले के लिए विभाग नई नीति में शराब दुकानों में बहुत बदलाव लाया गया है। इसे अंग्रेजी शराब दुकानों का आवंतन एक-एक कर लॉटरी के जरूर किया जाता है। जिसकी देशी शराब के लिए बाजार क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में शाम परावर्त वार समझ बना रखे हैं। एक समूह में देशी शराब की दो से तीन दुकानें हैं। नई व्यवस्था में अंग्रेजी शराब दुकानों की तर्ज पर सभी दुकानों को कम्पनिट कर एक-एक कर लॉटरी की ई-नीलामी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार दुकानों की ई-नीलामी इस्पात मंत्रालय के एमसटीसी पोर्टल से की जाएगी।

एक-एक दुकानों की ई-नीलामी

अंग्रेजी शराब दुकानों का आवंतन

एक-एक दुकानों का लॉटरी

जारी कर लॉटरी का तर्फ

इन्हें बहुत बदलाव हो रहा है।

जारी कर लॉटरी का तर्फ

जारी कर लॉट

